regional centre. To meet the infrastructural requirements in Aurangabad, we have already released a certain amount and we will see that a phases—it will be in phases—we complete the infrastructural facilities as soon as possible. I think the construction work for the hostel there would start very soon.

श्री राम गोपाल यादव : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस कार्य के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम-से-कम एक सेंटर के लिए सेंट्रल असिस्टेंस दी है जो कि मेरे गांव में है। श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली से सहायता मिलने में कितनी दिक्कतें होती हैं और किस तरीके से सहायता मिलती है। श्रीमन् मैं इसके साथ ही सवाल यह करना चाहता हूं कि एक तरफ गवनमेंट खेलकूद और इस सब को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम सेंटर्स खोलने के कार्यक्रम बना रही है दूसरी तरफ सारा हिन्दुस्तान जानता है कि इस देश में कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठन भी हैं जोकि बच्चों को तरफ हाफपेंट पहनाकर तमाम प्रकार की बातें सिखाते हैं और सांप्रदायिक विद्वेष जैसी बातें उनमें इंजेक्ट करते रहते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास इस तरह की कोई योजना है कि इस तरह के सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ उनकी कोई रायबल ऐसी संस्था और सेंटर्स खोले और जहां इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय कि वे इस तरह के तत्वों का मुकाबला कर सकें।

SHRI MUKUL WASNIK: There is generally a problem of politics in sports. The hon Member is asking me to get some sports into politics. I would like to mention here that we have various schemes to promote cer-tain rural tournaments in various disciplines in the backward areas. We also give some financial assistance to the federations in the field of sports promotion, and if there is any specific request from the htm. Member, I would look into it and see as to what we can do.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Percentage of Boys and girls not going to schools

564. SHRIMATI VEENA V)RMA:†

SHRI SUSHILKUMAR SAM-BHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HUMAN *BE*-SOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the percentage of girls and boys who were not going to schools during the years 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(b) what is the total estimated member of boys and girls in the age groups between 5—10 and 11—14 years not going to Schools in the rural and urban areas in each State and Union Territory; and

(c) what is the estimated number of these children covered by informal education schools?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RE SOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OP CULTURES (KUMARI SELJA): (a) and (b) According to data annually collected from States the percentage of children not attending primary and upper primary schools in 1990-91 to 1992-93 was as below:

Year	Primary	Upper Primary
1390-91 . .	19.57	36.17
1991-92 . .	18.21	35.07
1992-93 . .	15.85	28.33

Such data is not available for 1993-94 and for rural and urban schools separately.

†The Question was actually asked as the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

(c) Informal education for every individual goes on all the time in the social life. So every one is exposed to it. However the enrolment under non-formal education system was 63.75 lakhs in 1993-94.

SHRIMATI VEENA VERMA: Mr Chairman, Sir, education is the primary need of every human being and literacy is an indispensable tool for this purpose, which needs to be accorded a high priority, both as a human right and as a means of bringing about a transformation towards a more humane and enlightened socio-ty.

Despite the recognition of this fact, the number and percentage of children kept out of school remains high. The problem is more acute in respect of the female child, particularly, in the Northern and most populous States like Rajasthan, U.P. and Madhya Pradesh.

I would like to know whether any special actior plan is being contemplated to bring these States, which have Iess than 50 per cent literacy, under the 'Education For All" Programme. If so, what are the special features of such a plan?

KUMARI SELJA: Sir. Education For All is a multi-pronged strategy under which we have the 'Operation Blackboard', the total Literacy Campaign, the Primary Education Programme, etc. Now, under the Total Literacy Campaign, our focus has now been shifted towards the Hindi-speaking States which are more backward, as far as literacy is concerned.

SHRIMATl VEENA VERMA: Sir, since education has been recognised as an effective instrument for securing a status of; equality for women and persons belonging to the Backward Classes, including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I would like to know whether, in view of the observations made and decisions taken at the recent meeting of the 9 most populous countries on 'Education for Alt' any action plan has been drawn up, or. is being contemplated, to achieve universalisation of education within the next seven years; i.c. by 2000 A.D.; with a special thrust on education for the girl child and children of the Backward Classes.

KUMARI SELJA: Mr. Chairman, Sir. as I said, we have a multipronged strategy. The formal education is there. The non-formal education is there. The Total Literacy Campaign is there. Now, we have introduced another scheme, known as the District Primary Education Programme.

1 might say that most of these programmes focus, particularly, on the girl child because we find that the literacy rate amonsgt girls is less than in the case of boys. Therefore, under the new programme, to which 1 made a reference, namely, the District Primary Education Programme. the focus would be on areas where the female literacy rate is less than the national average. The focus would also he on areas which have a considerable Scheduled Castes/Schcduled Tribes population.

MR. CHAIRMAN: Shri Sushil Kumar Sambhajirao Shinde. Not here. Shri M. C. Meena.

श्री मूल चन्द मीणा : सभापति महोदय, सबको शिक्षित किया जाये। इस कार्यक्रम के माध्यम में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सरकार द्वारा जगह-जगह पर हर जिले में खोले गये। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा के ऊपर पिछले साल कितना पैसा खर्च किया गया और इस साल के अन्दर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? साथ ही यह भी बतायें कि आपके अनौपचारिक शिक्षा के जो केन्द्र हैं, उन केन्द्रों द्वारा वास्तविक रूप से, गांव में या जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग हैं या छात्र छात्रायें हैं, उनको वास्तविक रूप से शिक्षा दी जाती है या संख्या के आधार पर

फर्जी आंकड़े भर कर, यह साबित कर दिया जाता है कि यह अनौपचारिक केन्द्र चल रहे हैं ?

कुमारी शैलजा : यहां तक इनकी सेन्टर्स की बात है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्टेट से ही यह प्रोजेक्ट, जो नोन फोर्मल एजुकेशन के हैं, वहां से पास होकर आते हैं और जैसा स्टेट रिकमण्ड करती है, उनको ही वहां पर पास किया जाता है। जो इन्होंने एस्टीमेट के आंकड़े मांगे थे तो 1993-94 में 108 करोड़ रुपया खर्च किया गया और जब 1994-95 में 131 करोड़ का प्रावधान है।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से उत्तर के खण्ड "क" और "ख" के आलोक में जानना चाहूंगा कि देश के गांवों के उन लाखों बच्चों के लिये सरकार क्या सोच रही है, जो बचपन से भेड़, बकरी, गाय या भैंस चराकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं ? क्या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बिहार सरकार की तरह चरवाहा विद्यालय खोलने पर गंभीरता से विचार कर रही है ? (व्यवधान) . . . मैं कहूंगा:—

"जा के पांव न फटी बिवाई,
वो क्या जाने पीड़ पराई"

पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड के आलीशान भवन में रहने वाले गांव के दर्द को क्या जानिएगा, अहलुवालिया साहब ? जरा गांव के दर्द को जानिए कि गांव में क्या दर्द है, क्या पीड़ा है ? इसलिये इसका उत्तर दीजिये।

KUMARI SELJA: Sir, I think most, of us are from a rural background, and we arc closely connected with life in the rural araas.

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप हिन्दी में बोलिए न उन्होंने सवाल हिन्दी में पूछा है, जवाब हिन्दी में दीजिए।

KUMARI SELJA: Sir. most of our programmes are rural-based, as I have said, because most of aur population is in the rural areas. So most of our projects, for instance, Operation Black-board and others, are rural-based.

SHRI S. MADHAVAN: Sir, the wain-reason is poverty. In Tamil Nadu State we have introduced a mid-day meal*. scheme and we are spending crores of rupee:, every year for the education of the rural population. Will the Government consider framing a Centrail-spon-sofel scheme to help the State to have a mid-day meals scheme to help the rural population?

KUMARI SELJA: Sir. it is up te the respective States to have this kind of a programme.

श्री प्रो० वी० कोहली : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस समय देश में शैक्षिक वृत्ति से पिछड़े कितने राज्य हैं और शैक्षिक प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले दस वर्षों में इन राज्यों में से कितने राज्य शैक्षिक पिछड़ेपन की सीमा से ऊपर उठ आये हैं, बाहर निकल आये हैं ?

कुमारी शैलजा : सर, हम राज्यों के विकास से नहीं लेते कि कौन सा राज्य एजुकेशनली बैकवर्ड है, हम जो स्कीम बनाते हैं, वह एरिया के हिसाब से लेते हैं और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एरिया के हिसाब से हम स्कीम उनको देते हैं। अब यह स्टेट के ऊपर है कि वह अपनी किस डिस्ट्रिक्ट के लिये कौन सी स्कीम लेना चाहेगा, लेकिन जहां तक एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया की बात है, तो हिन्दी स्पीकिंग एरिया में इसको जो फिगर्स आई हैं, लिट्रेसी के मामले में, तो इसलिये आजकल फोकस हमारा हिन्दी स्पीकिंग एरियाज में है।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, अभी कुछ ही दिनों पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्वीकार किया कि उत्तरी भारत के राज्यों में शिक्षा का प्रतिशत

संभवत: 40 फीसदी है, जब कि राष्ट्रीय औसत 52 प्रतिशत है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि में राजस्थान राज्य ने अपने सम्पूर्ण बजट का 20 प्रतिशत भाग, यानी लगभग एक हजार करोड़ रुपया शिक्षा के लिये इयरमार्क किया है और वहां पर अभी एक नई योजना प्रारम्भ की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मां-बाप के बच्चों को निःशुल्क, मुफ्त में किताबें दी जायेंगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे उत्तरी भारत के राज्यों को शिक्षा के विकास की दृष्टि से, जो राज्य सरकारें अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायेंगी, उसमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेंगी?

और (ख) भाग मेरे प्रश्न का यह है कि आपने भाग "ख" के उत्तर में संख्या नहीं बताई है, उसे बताने की कृपा करें? आपका उत्तर अधूरा है, आपने केवल प्रतिशत बताया है, सम्पूर्ण संख्या नहीं बताई है,

So far as part two of the question is concerned. Sir, yon kindly verify this *fact.*

KUMARI SELJA: Sir, only absolute numbers can he supplied

MR. CHAIRMAN: They can be sup-plied. She will send it to yon later. All right?

SHRI SATISH AGARWAL: What shout the first part of the question? Will the Central Government come to the assistance of the States in the northern region, where the literacy percentage is below the national average, for providing financial assistance to those States in the northern sector which are providing free text-books to the poor children in the rural areas? Will you come to their aid?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

SHRl S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman has come to her aid!

MR. CHAIRMAN: That is the best answer!

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात और महाराष्ट्र में लघु सिंचाई योजनायें

*565. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "धारा" "जीवन धारा" और लघु सिंचाई योजनायें शुरू करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गुजरात और महाराष्ट्र को पर्याप्त धनराशि प्रदान की थी;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों द्वारा धारा के नाम से कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। मिलियन वैल्स योजना जो जवाहर योजना की एक उप योजना है, जीवन धारा के नाम से जानी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को लघु सिंचाई और मिलियन वैल्स योजना के लिए आवंटित की गयी निधियां निम्नवत हैं: